(b) to (d) Do not arise.

गोवा तट पर अवैध हथियारों का उतारा जाना

34. **श्री सूर्यभान पाटील वहाडणे:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 13 मार्च, 1998 को मुंबई से "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में गोवा तट पर अवैध हथियार उतरे "शीर्षक से प्रकाशित समाचार पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कोई कार्रवाई की गई है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) सरकार ने कथित प्रैस रिपोर्ट देखी है। गोवा तट पर बड़े पैमाने पर शस्त्र और गोला-बारूद इत्यादि उतारने के संबंध में कोई पुष्ट सूचना नहीं मिली है।

(ग) सरकार को स्थिति की जानकारी है तथा इस संबंध में उचित कदम उठा है। चौकसी बढ़ाने संबंधी सभी कार्यों का समन्वय करने के लिए राज्य सरकारों से नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने को कहा गया है। अन्य कदमों में आसूचना तन्त्र को सक्रिय बनाना, मौजूदा विनियमों को कड़ाई से लागू करना तथा संबद्ध केन्द्रीय और राज्य एजेन्सियों के बीच निकट समन्वय स्थापित करना शामिल है।

Talks with insurgents in North-East

35. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have any proposal to initiate talk with the insurgents to establish peace and normalcy in the North Eastern States;

(b) if so, the steps taken in that direction; and

(c) the detailed response of the insurgent outfits thereto?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) to (c) The Government are committed to hold talks with the insurgents to establish peace and normalcy in the North Eastern States. The Prime Minister in his Press Statement at Guwahati on 15th April, 1998 has stated "To all those who have strayed from the paths of togetherness, whether in Assam or other State of the North East, I extend an invitation; come forward; let us discuss, my Government is committed to holding talks to a restoration of peace; let us do so within the four corners of our Constitution."

No insurgent outfit has so far responded for talks within the parameters indicated by the Prime Minister.

आतंकवादियों द्वारा मारे गए अर्धसैनिक बलों के व्यक्ति

36. **श्री ओंकार सिंह लखावत:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान आतंकवादियों के साथ हुए विभिन्न मुकाबलों में सीमा सुरक्षा बल तथा सैनिक व अर्धसैनिक बलों के कितने सैनिक/सिपाही मारे गये; और

(ख) आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं में मारे गए ऐसे सैनिकों/सिपाहियों के परिवारजनों के पुनर्वास के लिए क्या-क्या कदम उठाये गये हैं तथा इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ों में सीमा सुरक्षा बल के 425 कार्मिकों सहित केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों के 738 कार्मिक मारे गए।

(ख) आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में अपनी ड्यूटी निभाते हुए मारे गए कार्मिकों के परिवारों को निम्नलिखित सहायता दी जाती है;

(i) केन्द्र सरकार द्वारा 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान।

(ii) केन्द्र सरकार कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना (सी०जी०ई०जी०आई०एस०) के अधीन देय बीमा राशि का भुगतान।

(iii) उदारीकृत पेंशन प्रदान करना।

(iv) अंशदायी लाभ निधि तथा विशेष राहत निधि आदि से वित्तीय सहायता।

(v) राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की गई अनुग्रहपूर्वक राशि का भुगतान।